



श्रीमद्भगवद्गीता के आलोक में सतत् विकास लक्ष्य क्रमांक-12 का बहुआयामी विश्लेषण

विनय कुमार सेठी *

श्वेता अवस्थी

भाषा एवं आधुनिक ज्ञान विज्ञान विभाग, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

Abstract

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2015 में '2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' को सम्पूर्ण विश्व के समक्ष इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया था कि मानव द्वारा सम्पादित की जाने वाली विकास सम्बन्धी गतिविधियाँ में भौतिक एवं आर्थिक प्रगति के साथ-साथ पर्यावरणीय संरक्षण, मानवीय गरिमा तथा सभी के लिए सामान अवसर जैसे महत्वपूर्ण पक्षों को भी समाहित किया जाए। इस वैश्विक कार्य-ढांचा में कुल 17 सतत् विकास लक्ष्य हैं, जिनमें लक्ष्य क्रमांक 12 'सतत् उपभोग एवं उत्पादन' से सम्बंधित है। यह लक्ष्य संसाधनों और ऊर्जा के कुशल उपयोग, टिकाऊ अवसंरचना, पर्यावरण-अनुकूलन तथा उन्नत जीवन-स्तर जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण पक्षों को समाहित करता है। श्रीमद्भगवद्गीता भारतीय ज्ञान प्रणाली के अंतर्गत एक ऐसा सशक्त ग्रन्थ है, जो मनुष्य को आध्यात्मिक चेतना प्रदान करने के साथ-साथ प्रकृति के साथ सहअस्तित्व तथा समाज के प्रति मानव के उत्तरदायित्व को भी रेखांकित करता है। इस लेख में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिपादित सतत् विकास लक्ष्य-12 की समुचित पूर्ति एवं प्राप्ति हेतु श्रीमद्भगवद्गीता में वर्णित उन कतिपय दार्शनिक प्रतिमानों को प्रस्तुत किया गया है, जो आधुनिक वैश्विक परिदृश्य में प्राचीन भारतीय चिन्तन की समकालीन प्रासंगिकता प्रस्तुत करते हैं।

Keywords: सतत् विकास लक्ष्य-12, सतत् उपभोग एवं उत्पादन, संसाधनों का कुशल उपयोग, पर्यावरणीय संरक्षण, श्रीमद्भगवद्गीता.

Received: 08/01/2026
 Accepted: 26/02/2026
 Published: 28/02/2026

*Corresponding Author:
 विनय कुमार सेठी

Email: vksethi@usvv.ac.in

वैश्विक विकास का मॉडल एक लम्बी अवधि तक गहरे द्वंद से ग्रसित रहा है, जिसके अंतर्गत मानव द्वारा आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकरण, नगरीकरण, मानवीय सुख-सुविधाओं एवं भौतिक सम्पदा के उत्पादन तथा विस्तार को विकास के मूलभूत तत्वों के रूप में स्थापित किया गया। इस विचारधारा में एक मुख्य दोष यह था कि मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की सीमित मात्रा, उनका पुनरुत्पादन, प्राकृतिक संतुलन एवं प्रकृति की वहन क्षमता जैसे महत्वपूर्ण पक्ष गौण कर दिए गए। ऐसी विचारधारा का परिणाम यह हुआ कि संसाधनों के अविवेकपूर्ण और अस्थायी उपयोग से गंभीर संसाधन-अभाव के साथ जलवायु-परिवर्तन और व्यापक पर्यावरणीय हास हुआ है, जिसने पृथ्वी तथा उस पर निवास करने वाले सभी जीवों के समग्र कल्याण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है (Parvatiyar and Sheth 2023, Warming 2023)।

इस गम्भीर एवं चिंताजनक विकास के प्रवाह में वर्ष 2015 को एक ऐतिहासिक और निर्णायक समय के रूप में देखा जाता है, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा '2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' को सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया। इस वैश्विक कार्य-ढांचा में कुल 17 सतत् विकास लक्ष्य एवं उनके 169 लक्ष्यांक निर्धारित किए गए। इन लक्ष्यों का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि मानव द्वारा किए जाने वाला विकास केवल भौतिक सम्पदा एवं आर्थिक समृद्धि तक सीमित न रहे, अपितु उसमें प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग, भावी पीढ़ियों के उपयोग के लिए उनकी उपलब्धता, मानव-गरिमा तथा सभी के लिए समान अवसर जैसे महत्वपूर्ण पक्षों को समाहित किया जाए (Siegel and Bastos-Lima 2020)। ये लक्ष्य बहुआयामी हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक तथा मानवीय प्रगति को प्राप्त करने हेतु

एक राजनीतिक प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करते हैं (Medina-Hernández et al. 2023)। विकास को अधिक व्यावहारिक, न्यायसंगत, समावेशी तथा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाये जाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत् विकास के इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वर्ष 2030 को लक्ष्य-वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया।

सतत् विकास के ये सभी लक्ष्य 'किसी को भी पीछे न छोड़ने' के सिद्धांत को आधार मानते हुए अनेक महत्वपूर्ण पक्षों को समाहित करते हैं, जिनमें गरीबी तथा भूख का उन्मूलन, स्वास्थ्य एवं कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जैव विविधता, जलवायु कार्यवाही, असमानताओं में कमी, सम्मानजनक कार्य, नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा, लैंगिक समानता, शांति, न्याय, सशक्त संस्थाओं की स्थापना आदि मुख्य हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत इन 17 सतत् विकास लक्ष्यों में लक्ष्य क्रमांक 12 'सतत् उपभोग एवं उत्पादन' से सम्बंधित है। आज जहां आर्थिक विकास की असंतुलित अवधारणा, अनियोजित नगरीकरण तथा औद्योगिकरण ने मनुष्य की जीवन शैली को अति-उपभोगवादी बना दिया है, ऐसी स्थिति में यह लक्ष्य-12 अत्यंत प्रासंगिक तथा महत्वपूर्ण बन जाता है (Amos and Lydgate 2020)।

लक्ष्य-12 को विशिष्ट लक्ष्यों (उप-लक्ष्य 12.1-12.8) में संरचित किया गया है और इसमें क्रियान्वयन के साधनों पर केंद्रित तीन अतिरिक्त लक्ष्य भी सम्मिलित हैं, जिनके साथ प्रत्येक के लिए सम्बन्धित संकेतक निर्धारित किए गए हैं। लक्ष्य-12 का मूल उद्देश्य संसाधनों और ऊर्जा के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करना, टिकाऊ अवसंरचना का विकास करना तथा सभी लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता, पर्यावरण-अनुकूल एवं गरिमापूर्ण रोजगार के अवसर और उन्नत जीवन-स्तर सुनिश्चित करना है (Omer and Noguchi 2020)। साथ ही साथ इसका व्यापक उद्देश्य यह है कि उत्पादन, वितरण तथा उत्पादों के उपयोग के प्रत्येक चरण में संसाधनों की उपयोग-दक्षता को निरंतर बढ़ाया जाए, जिससे कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया पर्यावरणीय-क्षरण

और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से स्वतंत्र हो सके। इस प्रकार यह लक्ष्य विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है, जिससे दीर्घकालिक, समावेशी और पर्यावरण-अनुकूल विकास सुनिश्चित किया जा सके (Sanyé-Mengual et al. 2019)।

लक्ष्य-12 के द्वारा एक महत्वपूर्ण तथ्य को रेखांकित किया गया है, जो कहता है कि मानव त्रुटिवश उपभोग को एक आर्थिक गतिविधि के रूप में देखता है, जबकि यह न्याय संगत नहीं है। इस लक्ष्य के अनुसार मानवीय उपभोग को सांस्कृतिक एवं नैतिक दृष्टि से देखे जाने की गहरी आवश्यकता है, क्योंकि जब तक मानव अपने उपभोग के तरीके तथा संसाधनों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं करेगा, तब तक सतत् विकास की अवधारणा सफल होना अत्यन्त दुष्कर है। दूसरे शब्दों में मानव की मानसिकता तथा उसके जीवन दृष्टिकोण का उसके द्वारा किए जाने वाले उत्पादन एवं उपभोग से सीधा सम्बन्ध होता है। अतः जब तक मानव अपने दृष्टिकोण में नैतिकता, संयम, विवेक एवं उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों को समाहित नहीं करेगा तब तक सतत् विकास लक्ष्य-12 की प्रभावी पूर्ति अत्यंत चुनौती पूर्ण बनी रहेगी।

भारतीय ज्ञान प्रणाली में मानवीय उपभोग को कभी भी असीम स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है। यह महान प्रणाली मानव को भोग एवं त्याग के मध्य संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देती है। इस सम्बन्ध में श्रीमद्भगवद्गीता की शिक्षाएं अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक हो जाती हैं (Shankaracharya 2019)। समाज का एक वर्ग श्री गीता को एक आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में देखता है, जबकि सत्य यह है कि यह ग्रंथ मानव के आचरण, उसकी अंतर्दृष्टि, प्रकृति के साथ उसके सहअस्तित्व तथा समाज के प्रति उसके उत्तरदायित्व का एक समग्र दिशा-निर्देशन प्रस्तुत करता है। श्री गीता का संपूर्ण दर्शन जिन बिंदुओं पर विशेष बल देता है उनमें संयम एवं अनासक्ति महत्वपूर्ण हैं। यदि विचार किया जाए तो आज मानव द्वारा संसाधनों का अंधाधुंध उपभोग इन दो जीवन मूल्यों

के अभाव में ही विकसित तथा पल्लवित हो रहा है। ऐसी स्थिति में लक्ष्य-12 की पूर्ति के लिए श्रीमद्भगवद्गीता की शिक्षाओं को एक प्रभावशाली आध्यात्मिक समाधान के रूप में स्वीकार किये जाने की महती आवश्यकता बन जाती है। श्री गीता का मूल विषय कर्म है और इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि यह कर्म केवल किसी क्रिया का किया जाना मात्रा नहीं है, अपितु इसमें विवेक एवं नैतिकता का समावेश होना अत्यंत आवश्यक है। चूँकि मानवीय उपभोग एवं उत्पादन दोनों ही कर्म के अंतर्गत आते हैं, अतः श्री गीता की शिक्षाओं से लक्ष्य-12 की पूर्ति के लिए वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली दिशा-निर्देश प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

प्रस्तुत लेख का उद्देश्य श्रीमद्भगवद्गीता के उन कतिपय दार्शनिक प्रतिमानों की प्रस्तुति करना है, जो लक्ष्य-12 की पूर्ति के आधुनिक वैश्विक परिदृश्य से सम्बन्धित हैं तथा प्राचीन भारतीय चिन्तन की समकालीन प्रासंगिकता स्पष्ट करते हैं।

सतत् विकास की अवधारणा संसाधनों के ऐसे उपभोग का समर्थन करती है, जो सांझा तथा नैतिक रूप से किया जाए। यह अवधारणा केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति को केन्द्रित नहीं करती अपितु यह भी सुनिश्चित करती है कि संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि वे भविष्य की पीढ़ियों के उपयोग के लिए भी उपलब्ध रहें (WCED, 1987)। इस अवधारणा के अनुपालन के लिए यह आवश्यक है कि संसाधनों का उपयोग केवल आत्म-केन्द्रित होकर न किया जाए अपितु उसमें पर-सेवा का भाव निहित होना चाहिए। श्री गीता इस सम्बन्ध में अत्यंत स्पष्ट संदेश देते हुए कहती हैं:

इष्टान्भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः।

तैर्दत्तान्प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः॥ (3.12)

एवं

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः।

भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्॥ (गीता 3.13)

उपर्युक्त श्लोकों के माध्यम से श्री गीता समझाती है कि प्रकृति द्वारा मानव की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का विधान किया गया है। अब यह मानव के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह प्रकृति से प्राप्त संसाधनों को उपयोग करते समय उनके प्रति आदर का भाव रखे। श्री गीता कहती है कि जो व्यक्ति प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों को प्रकृति को पुनः अर्पण किए बिना भोग करता है, वह 'चोर' की श्रेणी में आता है। इस भाव से स्पष्ट हो जाता है कि मानव द्वारा संसाधनों का उपभोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसा किया जाना केवल नैतिक दृष्टि से ही अनुचित नहीं होता अपितु सतत् विकास की दिशा में भी बाधा उत्पन्न करता है। इसके विपरीत जब प्रकृति से प्राप्त संसाधनों के उपभोग की क्रिया में, उन्हें समाज एवं प्रकृति को वापस लौटाने का भाव निहित रहता है तो वह पवित्र एवं सतत् बन जाता है। संसाधनों के उपभोग के प्रति ऐसा परिवर्तन निःसंदेह स्वागत योग्य है, तथापि इस हेतु विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वित और प्रभावी सहयोग आवश्यक है। इसमें केवल व्यवसाय और उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि नीतिनिर्माता, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, खुदरा विक्रेता, मीडिया तथा विकास सहयोग से जुड़ी संस्थाएं भी सम्मिलित होनी चाहियें। सभी के द्वारा मिलकर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सतत उपभोग और उत्पादन की दिशा में उठाए जाने वाले कदम सामूहिक रूप से लागू हों; व्यापक प्रभाव डालें और दीर्घकालिक रूप से पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक लाभ सुनिश्चित करें (Elia et al. 2020)।

श्री गीता भोजन को मात्र उदरपूर्ति का पदार्थ न मानते हुए, उसे 'प्रसाद' मानती है। वह मानव को निर्देशित करती है कि जो लोग पवित्र भाव से भोजन तैयार करते हैं तथा पहले उसे अर्पित करते हैं, वे दोषों से मुक्त हो जाते हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य मात्र इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोजन निर्माण अथवा उपभोग करते हैं, वे पाप कमाते हैं। लक्ष्य-12 आत्म-केन्द्रित उपभोक्तावाद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण स्थिरता एवं संकट का मूल कारण मानता है। श्री गीता हमें मार्गदर्शित करती है कि हमें

संसाधनों का उपभोग यज्ञ-भाव से करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से यदि हम भोजन की भांति संसाधनों को भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रसाद मान लें तो निश्चित रूप से उनका तिरस्कार करने में अथवा उनका अतिदोहन करने में हमें संकोच होगा। इसका वृहद् लाभ यह होगा कि हम उनके दोहन के साथ-साथ उनका संरक्षण एवं संवर्धन भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति में श्री गीता का यह संदेश आत्म-केंद्रित उपभोक्तावाद पर सीधा प्रहार करते हुए मानव को संयमित उपभोग की शिक्षा प्रदान करता है, जिससे संसाधनों के असमान वितरण और अपव्यय की समस्या का प्रभावशाली समाधान सम्भव है।

सतत् विकास के साथ-साथ लक्ष्य-12 'चक्रीय अर्थव्यवस्था' की अवधारणा का पुरजोर समर्थन करता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें संसाधनों के पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, मरम्मत और पुनर्निर्माण को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे अपशिष्ट के उत्पादन में गिरावट के साथ-साथ प्रदूषण में कमी तथा ऊर्जा की बचत से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण संभव हो सके (The Atlas of Sustainable Development Goals 2020)। यह अवधारणा हमें सिखाती है कि हम प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों को प्रदूषित करने से बचें और आवश्यकतानुसार उन्हें पुनः चक्रित करते रहें। मानव की ऐसी समस्त गतिविधियां जिनमें संयम तथा विवेक का अभाव होता है, वे वृहद् स्तर पर सामाजिक व्यवस्था के लिए हितकारी नहीं होती हैं। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं उनके पुनर्चक्रण पर विचार किए बिना मानव द्वारा उनका अविवेकपूर्ण दोहन इसका स्पष्ट उदाहरण है। श्री गीता उपर्युक्त समस्या का एक व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करते हुए कहती हैं:

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु।

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा॥ (गीता 6.17)

यह श्लोक जीवन के प्रत्येक पक्ष (आहार, विहार, कर्म, निद्रा, जागरण आदि) को केन्द्रित करते हुए उनमें संतुलन की आवश्यकता को नितांत

अनिवार्य बताता है। इस श्लोक में 'युक्त' शब्द की पुनरावृत्ति की गई है, जिसका आशय नियमित, संयमित एवं संतुलित व्यवहार से है। यहां युक्ताहार का संबंध केवल भोजन तक सीमित नहीं है, अपितु इसे सांकेतिक रूप से समस्त भौतिक उपभोग के पदार्थों (प्राकृतिक संसाधन सहित) के समुचित उपयोग के सन्दर्भ में प्रतिपादित किया जा सकता है। लक्ष्य-12 इसी भाव को प्रस्तुत करते हुए कहता है कि मानव द्वारा संसाधनों का उपभोग न तो अतिशय होना चाहिए न ही अपव्ययी, अपितु इसमें संसाधनों की उपलब्धता एवं पुनर्चक्रण को दृष्टिगत रखते हुए विकास की दीर्घकालिक स्थिरता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। श्री गीता की इस शिक्षा के अनुपालन से लक्ष्य-12 की संसाधनों के विवेकपूर्ण उपभोग, अपशिष्ट न्यूनीकरण और उनके सतत् उत्पादन की भावना को प्रभावशाली तरीके से पारित किया जा सकता है। व्यावहारिक स्तर पर इसके अनुपालन के लिए एक व्यापक और प्रणालीगत दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक स्तर यथा-निर्माता, वितरक, खुदरा विक्रेता और अंतिम उपभोक्ता, के बीच निरन्तर और समन्वित सहयोग स्थापित किया जाए। यह सहयोग न केवल उत्पादन और वितरण की दक्षता बढ़ाने के लिए आवश्यक है, अपितु संसाधनों के सतत् उपयोग, अपशिष्ट कम करने, पर्यावरणीय संरक्षण और समाज के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार का समन्वय सभी हितधारकों को जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे सतत् उपभोग और उत्पादन की दिशा में दीर्घकालिक और प्रभावी प्रगति संभव हो सके (Sudusinghe and Seuring 2022)।

सर्वविदित है कि सतत् विकास हमें वर्तमान पीढ़ी के साथ-साथ भविष्य की पीढ़ियों के प्रति संवेदनशील होने का विशेष संकेत करता है (WCED, 1987)। किंतु यदि व्यावहारिक स्तर पर देखा जाए तो स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है। ऐसा इसलिए है कि विश्व के अनेक विकसित राष्ट्र प्राकृतिक संसाधनों पर अपना नैतिक अधिकार मानते हुए उनका

अधिक और असंतुलित उपयोग करते हैं, जबकि विकासशील तथा अन्य गरीब देश आधुनिक तकनीक एवं धन के अभाव में संसाधनों की कमी को झेलते हैं। ऐसी असमानता के चलते वैश्विक स्तर पर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पक्षों में विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य मतभेद दृष्टिगत होने लगते हैं।

जहाँ कार्बन फुटप्रिंट सभी देशों के लिए चिंता का विषय है, वहीं उत्सर्जन की मात्रा विकसित और विकासशील देशों के बीच काफी भिन्न होती है। विकसित देशों में उच्च औद्योगिकीकरण और ऊर्जा खपत के कारण प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट अधिक होता है, जबकि विकासशील देशों में औद्योगिक गतिविधि और ऊर्जा उपयोग कम होने के कारण यह अपेक्षाकृत कम होता है (Shanfei et al. 2024)। धन के बल एवं सत्ता के मद के वशीभूत होकर विकसित देश उद्योग, उत्पादन, परिवहन व्यवस्था तथा ऊर्जा उपभोग से जुड़ी गतिविधियों में जीवाश्म ईंधन, जल, ऊर्जा, खनिज तथा अन्य संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं। उनके इस अनैतिक कृत्य के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं यथा- जलवायु परिवर्तन, ओजोन-क्षरण, प्राकृतिक आपदाओं आदि का नकारात्मक प्रभाव उन विकासशील एवं गरीब देशों पर अधिक होता है, जो दोषी नहीं हैं। यदि इस समस्या के समाधान पर चर्चा की जाए तो निश्चित रूप से सम्बन्धित विकसित देशों का उत्तरदायित्व तय होता है।

ऐसी स्थिति में विकसित देशों का यह उत्तरदायित्व बन जाता है कि वे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की सीमाएं निर्धारित करें, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के उपयोग के लिए बनी नीतियों एवं कानूनों का निष्ठा से पालन करें तथा जल-संरक्षण, कचरा प्रबंधन आदि पक्षों से जुड़ी उन्नत तकनीकों को विकासशील देशों को सुलभता से उपलब्ध कराएं। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि यदि विकसित देश संसाधनों के अति उपभोग एवं संग्रह की नीति का परित्याग कर दें तो लक्ष्य-12 की पूर्ति सहज एवं सरल हो सकती है। श्रीमद्भगवद्गीता की शिक्षा इस दिशा में अत्यंत सार्थक तथा प्रासंगिक दिखती है। श्री कृष्ण कहते हैं:

नात्यश्रतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्चतः।

न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन॥ (6.16)

इसका अर्थ है कि अधिक भोजन करने वाले अथवा बहुत कम खाने वाले के लिए, अधिक सोने अथवा अधिक जागृत रहने वाले के लिए योगी बनना संभव नहीं है। लक्ष्य- 12 के आलोक में यहां भोजन की प्रत्यक्ष तुलना संसाधनों के उपयोग से की जा सकती है।

व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो उपर्युक्त श्लोक संसाधनों के उपभोग पर नियंत्रण की शिक्षा देता है। साथ ही साथ यह संसाधनों के संरक्षण तथा पर्यावरण हितैषी जीवन शैली अपनाए जाने का एक व्यावहारिक आधार भी प्रस्तुत करता है। श्री गीता के अध्याय 12 के श्लोक 14 में वर्णित अंश- 'सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः' भी मानव को इस नैतिकता को अपनाने की ओर प्रेरित करता है। यहां यह स्पष्ट है कि संसाधनों का अत्यधिक एवं अनुचित उपभोग पर्यावरणीय असंतुलन को बढ़ावा देता है (Gasper et al. 2019) तथा वर्तमान में इसके दोषी अनेक ऐसे विकसित देश हैं, जो या तो प्राकृतिक संतुलन के प्रति उदासीन हैं अथवा हठधर्मी। यदि मानव श्री गीता के उपर्युक्त मर्म को अपने व्यावहारिक जीवन में आत्मसात कर ले तो विकसित देशों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अति-संग्रह तथा -उपभोग के कारण उत्पन्न समस्याओं को सुलझाने की दिशा प्रशस्त की जा सकती है।

श्री गीता के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 20 में वर्णित 'लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि' शिक्षा लक्ष्य-12 की पूर्ति का एक सशक्त समाधान प्रस्तुत करती है। सर्वविदित है कि सतत् विकास का सिद्धान्त उस पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति का भी ध्यान रखना है, जिनका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। अंतरपीढ़ी न्याय का यह सिद्धान्त मानव को निर्देशित करता है कि वह संसाधनों का इस प्रकार अति-दोहन न करें कि भविष्य की पीढ़ियां उनके उपयोग से वंचित रह जाएं। यद्यपि यह महत्वपूर्ण शिक्षा अनुकरणीय है परन्तु मानव द्वारा सदैव इसकी व्यापक अवहेलना की गयी

है। भारत की भूमि से चीता, मालाबार लार्ज स्पॉटेड सीविट, पिंक हेडेड डक, हिमालयन क्वेल, गंगा शार्क जैसी अनेक पशु-पक्षियों की प्रजातियों की विलुप्ति अथवा उनके अस्तित्व पर मंडराता भारी संकट इसके ज्वलंत तथा प्रमाणिक उदाहरण हैं। श्री गीता में वर्णित लोक संग्रह का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि कर्म केवल व्यक्तिगत हित तक सीमित नहीं होना चाहिए अपितु उसे करते समय कर्ता के द्वारा समाज तथा भविष्य का व्यापक हित भी संज्ञान में लिया जाना चाहिए। इस प्रकार सतत् उपभोग की यह शिक्षा निश्चित रूप से लक्ष्य-12 की पूर्ति के लिए मानव को न केवल प्रोत्साहित करती है अपितु उसके अनुपालन का एक नैतिक एवं व्यावहारिक धरातल भी उपलब्ध कराती है (Fischer et al. 2023)।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि श्रीमद्भगवद्गीता की शिक्षाओं तथा सतत् विकास लक्ष्य क्रमांक 12 के मध्य एक गहरी निकटता एवं समानता है। यहां यह बताना महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह समानता केवल वैचारिक स्तर तक सीमित नहीं है अपितु भिन्न कालखण्ड एवं अलग-अलग भाषाओं की यह अभिव्यक्ति असंतुलित उपभोग एवं उत्पादन की मूल समस्या को प्रभावशाली तरीके से सम्बोधित करती है। जहाँ एक ओर सतत् विकास मानव सुख और जीवन-गुणवत्ता को पारिस्थितिक और सामाजिक प्रणालियों के संरक्षण के साथ जोड़ता है तथा यह स्वीकार करता है कि विकास तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक पर्यावरण स्वस्थ और समाज न्यायपूर्ण न हो (Max-Neef and Smith 2011, UNGA 2015), वहीं दूसरी ओर श्री गीता की शिक्षाएं संतोष, संयम, लोकसंग्रह जैसे उच्च स्तरीय मूल्यों को मानव के समक्ष प्रस्तुत करती हैं तथा सतत् विकास के अनुपालन को सशक्त करती हैं। श्री गीता की शिक्षाएं मानव-समाज को एक ऐसा नैतिक, दार्शनिक तथा व्यवहारिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराती हैं, जो लक्ष्य-12 की आत्मा से अत्यंत निकटता प्रदर्शित करता है। अब यह मानव का उत्तरदायित्व बन जाता है कि वह इन शिक्षाओं को गंभीरता से समझे, उन्हें आत्मसात करे

तथा व्यक्तिगत स्तर पर लक्ष्य-12 में निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुपालन में अपनी सक्रिय तथा सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करे।

सन्दर्भ सूची:

Amos, R., and E. Lydgate. "Trade, Transboundary Impacts and the Implementation of SDG 12." *Sustainability Science*, vol. 15, 2020, pp. 1699–1710.

Elia, G., et al. "Building Responses to Sustainable Development Challenges: A Multistakeholder Collaboration Framework and Application to Climate Change." *Business Strategy and the Environment*, vol. 29, 2020, pp. 2465–2478.

Fischer, M., et al. "Sustainable Consumption." *Springer Encyclopedia of Sustainability Science and Technology*, 2023, doi:10.1007/978-3-031-25397-3_7.

Gasper, Des, et al. "The Framing of Sustainable Consumption and Production in SDG 12." *Global Policy*, vol. 10, 2019, pp. 83–95.

Max-Neef, Manfred, and Philip B. Smith. *Economics Unmasked: From Power and Greed to Compassion and the Common Good*. Bloomsbury Publishing, 2011.

Medina-Hernández, Edith Johana, et al. "The Current Status of the Sustainable Development Goals in the World." *Development Studies Research*, vol. 10, no. 1, 2023, article 2163677.

Omer, M. A., and Takashi Noguchi. "A Conceptual Framework for Understanding the Contribution of Building Materials in the Achievement of Sustainable Development Goals (SDGs)." *Sustainable Cities and Society*, vol. 52, 2020, article 101869.

Parvatiyar, Atul, and Jagdish N. Sheth. "Confronting the Deep Problem of Consumption: Why Individual Responsibility for Mindful Consumption Matters." *Journal of Consumer Affairs*, vol. 57, 2023, pp. 785–820.

Sanyé-Mengual, E., et al. "Assessing the Decoupling of Economic Growth from Environmental Impacts in the European Union: A Consumption-Based Approach." *Journal of Cleaner Production*, vol. 236, 2019, article 117535.

Shankaracharya. *Shrimad Bhagavad Gita Bhashya*. Gita Press, 2019.

Siegel, Karen, and Mairon Bastos Lima. "When International Sustainability Frameworks Encounter Domestic Politics: The Sustainable Development Goals and Agri-Food Governance in South America." *World Development*, vol. 135, 2020, article 105053.

Sudusinghe, J. I., and Stefan Seuring. "Supply Chain Collaboration and Sustainability Performance in Circular Economy: A Systematic Literature Review." *International Journal of Production Economics*, vol. 245, 2022, article 108402.

United Nations. *Our Common Future*. World Commission on Environment and Development, 1987.

United Nations General Assembly. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. 2015.

Warming, G. "Global Environmental Issues: Global Warming, Biodiversity, Resource Scarcities." *Understanding Globalisation: Challenges and Prospects*, edited by Kamal Kumar, Routledge, 2023, pp. 188–209.

World Bank. *The Atlas of Sustainable Development Goals 2020*. 2020, datatopics.worldbank.org/sdgoalatlas/.

Zhang, Shanfei, et al. "Comparing Developed and Emerging Nations' Economic Development with Environmental Footprint for Low-Carbon Competitiveness." *Heliyon*, vol. 10, 2024, article e34039.